राष्ट्रीय चैंपियन मॉडलः

क्या अगली पीढ़ी के एशियाई मॉडल के रूप में अपने आप को पेश कर पायेगा

इंडियन एक्सप्रेस

पेपर-III
(भारतीय अर्थव्यवस्था)

उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे ने जादू की गोली के पहलुओं को अपनाया है साथ ही यह एक राष्ट्रीय आकांक्षा के रूप में काम करता है राष्ट्रीय प्रगति का एक बैरोमीटर, रोजगार सृजन के लिए एक तंत्र, निजी निवेश में भीड़ के लिए एक वाहन और बहुत कुछ। इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रदर्शन अच्छा और एक आवश्यकता दोनों बन गया है, यह एक भारी बोझ है।

बुनियादी ढाँचे के प्रावधान पर दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं:-

1. पहला, इसे न्यूनतम पैमाने पर बनाने की जरूरत है, जो इसे महंगा बनाता है और
2. दूसरा, इसमें अक्सर एक अच्छा सार्वजनिक घटक होता है जो व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए बुनियादी ढांचे के निजी मूल्य की तुलना में बुनियादी ढाँचे के सामाजिक मूल्य को अधिक बनाता है। इसलिए, निजी निवेशकों को ऐसे निवेश अपेक्षाकृत लाभहीन लगते हैं।

बुनियादी ढांचो का वित्तपोषण

बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण इस प्रकार कर राजस्व या सरकारी उधार पर निर्भर है। लेकिन यह एक शातिर जाल के तत्वों का परिचय देता है। गरीब अर्थव्यवस्थाएं कम कर राजस्व उत्पन्न करती हैं, जो बुनियादी ढांचे के निवेश को सीमित करती हैं। यह निजी निवेश के रिटर्न को कम कर देता है, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास पर असर पड़ता है और देश को गरीब बना देता है। घरेलू स्तर पर सार्वजनिक उधारी बढ़ाकर चक्र को तोड़ने का प्रयास निजी निवेश को बाहर कर देता है।

सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मॉडल द्वारा बुनियादी ढांचे का विकास

कोई इसके आसपास कैसे पहुंच सकता है? एक संभावना बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए लक्षित सब्सिडी प्रदान करके निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। भारत ने सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मॉडल की शुरुआत करके 2000 के दशक की शुरुआत में यह कोशिश की। इस व्यवस्था ने सरकार को भूमि और प्राथमिक वस्तुओं के अधिग्रहण की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की। इन निहित और स्पष्ट सब्सिडी के साथ, निजी क्षेत्र को निर्धारित समय के लिए परियोजनाओं का निर्माण और चलाने के लिए मिला। जबकि कार्यक्रम के तहत बहुत सारे बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया था, पीपीपी मॉडल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के दिवालिया होने, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों और 2014 में सरकार में बदलाव के साथ गैर-निष्पादित संपत्तियों के हिमस्खलन में समाप्त हो गया।

'पीपीपी मॉडल' को संशोधित कर 'राष्ट्रीय चैंपियन मॉडल' लाया गया

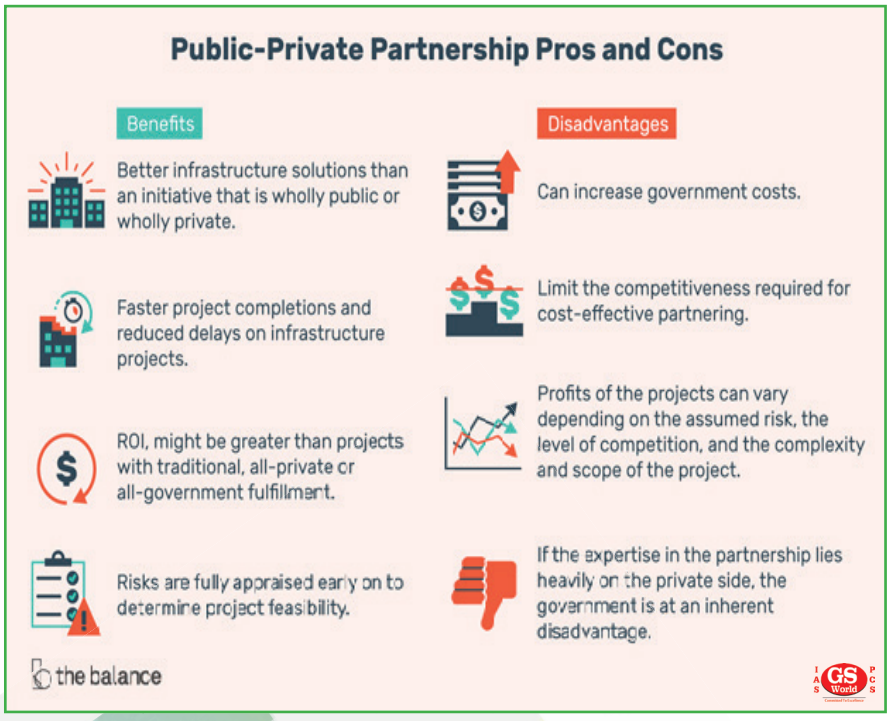

पिछली सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं में से एक के निहित समर्थन में, एनडीए सरकार ने भी बुनियादी ढांचे को एक प्रमुख अड़चन के रूप में चिन्हित किया है। हालांकि, इसने कुछ चुने हुए औद्योगिक घरानों को सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, ऊर्जा और संचार के लिए भारी मात्रा में बुनियादी ढांचे का प्रावधान करके पीपीपी दृष्टिकोण को संशोधित किया है। यह "राष्ट्रीय चैंपियन" मॉडल है जहां सरकार अपनी विकास प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए कुछ बड़े समूह चुनती है। यह मॉडल बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण की कमी को कैसे पूरा करता है? सरकार द्वारा पहचानी गई परियोजनाओं के निर्माण के लिए राष्ट्रीय चैंपियन को प्रोत्साहित करने के लिए, अभी भी लागत को कवर करने के लिए सब्सिडी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह पीपीपी मॉडल की तरह ही है।

राष्ट्रीय चैंपियन मॉडल में नया क्या है?

राष्ट्रीय चैंपियन मॉडल के तीन नए पहलू हैं:-

सबसे पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रिटर्न जनरेट करने में लंबा समय लगता है, जो कम होने की भी प्रवृत्ति होती है। ऐसी परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, इन चैंपियनों को मजबूत नकदी प्रवाह वाली मौजूदा परियोजनाओं पर नियंत्रण देने की आवश्यकता है। इससे संगुटों को उनके खातों में ऋणात्मक नकदी प्रवाह परियोजनाओं को रखते हुए उनके लक्षित कुल प्रतिफल को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

दूसरा, सरकार की राष्ट्रीय विकास नीति के साथ चैंपियनों का सार्वजनिक जुड़ाव घरेलू और विदेशी अनुबंध प्राप्त करने में चैंपियनों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उत्पन्न करता है। यह भी कुछ स्थिर नकदी प्रवाह की गारंटी देता है। तीसरा, कुछ नकदी-समृद्ध परियोजनाओं तक पहुंच इन राष्ट्रीय चैंपियनों को संपार्श्विक के रूप में इन संस्थाओं का उपयोग करके बाहरी ऋण बाजारों से उधार लेने की अनुमति देती है। यह निजी निवेश के लिए घरेलू बचत को मुक्त करते हुए अन्य परियोजनाओं के वित्त की लागत को कम करता है, यह चतुर और अभिनव है।

राष्ट्रीय चैंपियन मॉडल में समस्याएं क्या हैं?

"राष्ट्रीय चैंपियन" मॉडल में चार स्पष्ट समस्याएं हैं :-

सबसे पहले, सरकारी नीतियों के साथ इन समूहों का सीधा जुड़ाव बाजारों और नियामकों के लिए उन्हें असफल होने के लिए बहुत बड़ा मानने की क्षमता पैदा करता है। यह बाजार उन्माद, समस्याओं की देरी से खोज, और क्षेत्रीय समस्याओं के स्पिलओवर को प्रणालीगत झटकों में खोलने का द्वार खोलता है। अडानी कंपनियों की हालिया मुसीबतों से इसे बड़ी राहत मिली है।

दूसरा, यह जिस बाजार संकेन्द्रण को प्रोत्साहित करता है, वह अर्थव्यवस्था-व्यापक स्तर पर दक्षता और उत्पादकता के लिए अक्सर बुरा हो सकता है।

तीसरा, बड़े पैमाने पर नकदी प्रवाह उत्पन्न करने के लिए परियोजनाओं में जितना अधिक समय लगेगा, चैंपियनों को अतिरिक्त नकदी प्रवाह तक पहुँच प्रदान करने के लिए राज्य की उतनी ही अधिक आवश्यकता होगी। यह देश को एक औद्योगिक कुलीन तंत्र में बदलने का जोखिम उठाता है।

चौथा, बाजार पहुँच और चयनात्मक विनियामक सहनशीलता के संदर्भ में एक असमान खेल के मैदान की संभावना विदेशी निवेशकों के लिए एक महत्त्वपूर्ण बाधा बन सकती है, एक ऐसा परिणाम जिसे भारत वहन नहीं कर सकता है।

सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मॉडल क्या है?

- पीपीपी मॉडल आज के दौर की सबसे नवीन साझेदारी है इस सार्वजनिक-निजी भागीदारी में एक सरकारी एजेंसी और एक निजी क्षेत्र की कंपनी साथ आते हैं। ये दोनों कंपनियां आपसी सहयोग से विभिन्न परियोजनाएँ जैसे सार्वजनिक पार्क, परिवहन नेटवर्क जिसमें रोड, रेल, ब्रिज आदि शामिल हैं। इन सब का निर्माण तेजी से करते हैं। इस मॉडल से सरकार पर वित्तीय बोझ कम होता है क्योंकि निजी कंपनियों के प्रवेश से उनकी भी हिस्सेदारी इस मॉडल में होती है।
- पीपीपी मॉडल कई प्रकार के होते हैं जैसे बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी), बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ), बिल्ड-ऑपरेट-लीज-ट्रांसफर (बीओएलटी), डिजाइन-बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (डीबीएफओटी), लीज-डेवलप- ऑपरेट (एलडीओ), ऑपरेट-मेंटेन-ट्रांसफर (ओएमटी), आदि शामिल हैं। ये सारे मॉडल मौजूदा दौर में कृषि को छोड़कर अन्य सेक्टर्स में लागू किए जा चुके हैं जिससे आज बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

राष्ट्रीय चैंपियन मॉडल के पीछे सोच क्या है?

एक गहरा मुद्दा इस प्रस्ताव के संबंध में है कि बुनियादी ढांचा प्रावधान भारत की विकास आकांक्षाओं का समाधान है। प्रचलित सोच यह है कि एक बार बंदरगाह, सड़कें, बिजली आदि स्थापित हो जाने के बाद निजी निवेश आएगा। यदि 2000 के दशक की शुरुआत में बुनियादी ढाँचा निवेश में उछाल का अनुभव कोई मार्गदर्शक है, तो यह धारणा समस्याग्रस्त है। बिजली क्षेत्र में समस्या उत्पादन नहीं थी, बल्कि बिजली वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान वसूल करने में असमर्थता थी। यह प्रभावी मांग की समस्या है।

निष्कर्ष

भारत अपने विकास पथ में एक मोड़ बिंदु पर है। जिसने घरेलू मांग-संचालित उत्पादन संरचना पर आधारित एक विकास मॉडल पर दांव लगाया है जो नरम और कठोर बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है जो कुछ हाथों में भारी रूप से केन्द्रित है। अगर यह काम करता है तो इसे अगली पीढ़ी के एशियाई मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। अन्यथा, यह कई पीढ़ियों के लिए सावधानी की एक अच्छी कहानी प्रदान करेगा।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मॉडल पर सरकारी एजेंसी और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ कम होता है।
2. राष्ट्रीय चैंपियन मॉडल के तहत देश के बुनियादी ढाँचे का विकास कुछ चुने हुए औद्योगिक घरानों द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements–

1. The public-private-partnership (PPP) model allows the government agency and the private sector to work together and reduce the financial burden on the government.
2. Under the national champion model, the country's infrastructure is developed by a select few industrial houses.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 'राष्ट्रीय चैंपियन मॉडल' क्या है? यह सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मॉडल से किस तरह भिन्न है तथा इसके लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए। (250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- 'राष्ट्रीय चैंपियन मॉडल' क्या है तथा यह किस तरह काम करता है बताएं।
- यह सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मॉडल से किस तरह अलग है बताएं।
- यह बुनियादी ढांचे के विकास में किस तरह मदद कर सकता है तथा इससे जुड़ी हानियों को भी बताएं।
- संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।